

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है। विस्तृत दिशा निदेश यथा दायित्व एवं कर्तव्य विभागीय वेबसाईट ([www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in)) पर उपलब्ध है।


महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-27(1) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के सभी जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट [rdd.bih.nic.in](http://rdd.bih.nic.in) पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 28.02.2019 को संध्या बजे 06:00 बजे तक होगी।

नियुक्ति की शर्तें-

1. लोकपाल (Ombudsman) का चयन दो वर्षों के लिए होगी। उनके द्वारा संपादित कार्यों के समीक्षोपरांत उन्हें अधिकतम 2 बार एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. लोकपाल (Ombudsman) के लिए प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 20000/- रूपये प्रतिमाह देय होगा। जाँच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा।
4. आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों।

**योग्यता:-** अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो तथा लोक प्रशासन यथा अपर समाहर्ता एवं उच्च स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, विधि यथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च स्तर के सेवानिवृत्त विधि पदाधिकारी, अभियंत्रण सेवा यथा अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के सेवानिवृत्त अभियंता, सामाजिक कार्यों में संबद्ध व्यक्ति जो 20 वर्षों से अन्यून ख्याति प्राप्त NGO के कार्य अनुभव रखते हो।

**उम्र सीमा:-** अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 1.04.2019 के आधार पर)

  
संयुक्त सचिव  
ग्रामीण विकास विभाग